

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद की पत्रकार वार्ता का संशोधित  
प्रतिलेख: 6 दिसंबर, 2024

**भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी:**

श्री शक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. माइकल डी. पत्रा - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री स्वामीनाथन जे. - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. ओ. पी. मल्ल - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. राजीव रंजन - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

**संचालक:**

श्री पुनीत पांचोली - भारतीय रिज़र्व बैंक

**पुनीत पांचोली:**

नमस्कार। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद की इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे साथ भारत के रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री शक्तिकांत दास; उप गवर्नर डॉ. एम.डी. पत्रा, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. उपस्थित हैं। हमारे साथ कार्यपालक निदेशक डॉ. ओ. पी. मल्ल और कार्यपालक निदेशक डॉ. राजीव रंजन तथा रिज़र्व बैंक के अन्य सहयोगी भी मौजूद हैं। महोदय, शुरुआत करने के लिए, मैं आपसे अपने उद्घाटन विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध करूंगा। इसके बाद, हम प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करेंगे।

**शक्तिकान्त दास:**

मैं शुरुआत में पांच अवलोकन प्रस्तुत करना चाहूंगा:

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) हाल ही में असंतुलित हुई महंगाई और विकास के बीच संतुलन को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- रिज़र्व बैंक महंगाई-विकास संतुलन को बहाल करने की स्थितियां बनाने के लिए अपने विभिन्न नीतिगत उपकरणों का उपयोग करेगा।
- लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे की विश्वसनीयता को बनाए रखने की आवश्यकता है। सतत विकास के हित में महंगाई को कम किया जाना चाहिए।
- विवेक, व्यावहारिकता और समयबद्धता, रिज़र्व बैंक के भविष्य के कार्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहेंगे।

- यह सब महंगाई-विकास की स्थितियों के विश्लेषण और तदनुसार कार्य करने के बारे में है। कार्यों की समयबद्धता ही कुंजी है। धन्यवाद।

### **पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। शुरू करने से पहले, मैं यहां उपस्थित मीडिया के मित्रों से अपने बारी का इंतजार करने का अनुरोध करूंगा। आप गलियारे में अपने सहयोगियों को देख सकते हैं। उनके पास माइक हैं। वे आपको माइक देंगे, कृपया माइक में ही बोलें क्योंकि अन्यथा आप बाहर बैठे लोगों को सुनाई नहीं देंगे। और समय की बचत के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कृपया प्रति व्यक्ति एक प्रश्न तक सीमित रहें और यदि समय अनुमति दे, तो हम दूसरे प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। सर, आज मीडिया के 24 प्रतिभागी हैं और आपकी अनुमति से, मैं उनके नाम पुकारना शुरू करूंगा। तो, मैं दूरदर्शन के श्री योगेश से शुरू करता हूं।

### **योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन:**

शुभ अपराह्न, सर। अवसर देने के लिए धन्यवाद। सर, जीडीपी के अनुमान में कमी के बावजूद, दरें मूल रूप से बनाए रखी गई हैं। यथास्थिति बनाए रखी गई, लेकिन नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंकों से कम किया गया। इसके पीछे क्या सोच है? धन्यवाद।

### **शक्तिकान्त दास:**

मुझे लगता है कि मैंने इसे उस वक्तव्य में विस्तार से समझाया है जो मैंने आज सुबह पेश किया था। और विकास के संबंध में, इस वर्ष का दूसरा छमाही पहले छमाही की तुलना में बेहतर दिख रहा है। इस वर्ष की पहली तिमाही में, कुछ ऐसे मुद्दे थे जो देशव्यापी चुनावी सीजन के साथ संयोग में थे। संभवतः इसने विशेष रूप से सरकारी व्यय को प्रभावित किया। दूसरी तिमाही में, मंदी के कारणों की हमने पहले ही व्याख्या की है। मानसून, आप जानते हैं, लगातार मानसून की बारिश ने भी गतिविधियों को प्रभावित किया, विशेष रूप से खनन और बिजली मांग में। विनिर्माण क्षेत्र भी धीमा रहा। इसलिए, मैंने समझाया है कि हम इस वर्ष दूसरे छमाही को पहले छमाही की तुलना में बेहतर क्यों उम्मीद करते हैं। और महंगाई पर, मैंने एक रास्ता भी दिया है। हमने एक रूपरेखा भी दी है।

इसलिए, हमें अधिक विश्वसनीय साक्ष्यों की आवश्यकता है कि चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, कि घटनाक्रम की दिशा, विकसित हो रही स्थितियों की दिशा, और परिदृश्य हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप चल रहा है। और फिर, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया, यह समयबद्धन का प्रश्न है। आपको अपने कार्यों का उचित समय पर निर्धारण करना

होगा। जब किसी विशेष कार्य का समय हो, चाहे वह दर में कटौती हो, तरलता संबंधी कार्य हो, या जो भी कार्य हो, उनका समयबद्धन अच्छी तरह से होना चाहिए। परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उनका समयबद्धन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे सबसे अधिक प्रभावी और प्रभावशाली हों।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न बिजनेस स्टैंडर्ड से श्री मनोजित साहा का होगा।

**मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:**

धन्यवाद, सर। मैं वह प्रश्न पूछना चाहूंगा जो सभी के मन में है। क्या नीति बैठक शुरू होने से पहले, कम से कम अनौपचारिक रूप से, सरकार की ओर से आपको कोई संकेत मिला है कि क्या आप इस कार्यकाल को जारी रख रहे हैं? मेरे पास आज एक और प्रश्न भी है।

**शक्तिकान्त दास:**

क्या यही आपका एकमात्र प्रश्न है?

**मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:**

नहीं, मेरे पास एक और प्रश्न है।

**शक्तिकान्त दास:**

नहीं। कृपया हम मौद्रिक नीति पर ही चर्चा करें। आप मौद्रिक नीति पर अपना प्रश्न पूछें। अन्यथा, आप मौद्रिक नीति पर प्रश्न पूछने का अवसर खो देंगे। अतः आप चुनें कि आप क्या पूछना चाहते हैं। यह आपकी पसंद है। मैं पहले प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ, लेकिन यह आपकी पसंद पर निर्भर है।

**मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:**

कृपया पहले प्रश्न का ही उत्तर दें।

**शक्तिकान्त दास:**

मैं आपको कोई सुर्खी नहीं दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम मौद्रिक नीति पर ही चर्चा करें। धन्यवाद। लेकिन कृपया आप अपना मुख्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

**मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:**

मेरा प्रश्न यह था कि आपने दूसरी तिमाही (ति2) के लिए विकास का अनुमान इतना गलत कैसे लगाया? आपने अक्टूबर में भी 7% का अनुमान लगाया था, जबकि यह 5.4% रहा। तो वास्तव में अनुमान में क्या गलत हुआ?

**शक्तिकान्त दास:**

मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उप गवर्नर, माइकल पत्रा जी को आमंत्रित करता हूं।

**माइकल डी. पत्रा:**

इस पर प्रेस में पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। यदि आप मांग पक्ष को देखें, तो मुख्य समस्या निवेश की है। आपूर्ति पक्ष पर, मुख्य समस्या विनिर्माण की है और ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। विनिर्माण में, सबसे बड़ी समस्या बिक्री वृद्धि में गिरावट है, जो यह दर्शाती है कि महंगाई का प्रभाव शहरी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। अतः जब बिक्री वृद्धि कम होती है, तो कंपनियां नई संपत्तियों में निवेश नहीं करना चाहतीं क्योंकि वे मांग को मध्यम देखती हैं और इसे मौजूदा क्षमता से पूरा किया जा सकता है। चूंकि वे नई क्षमता सृजन में संलग्न नहीं होना चाहतीं, इसलिए निवेश कम हो गया है। अतः वृद्धि में अंतर्निहित मंदी का कारण महंगाई है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, महोदय। अब मैं ईटी नाउ से श्री अंकुर मिश्रा को आमंत्रित करता हूं।

**अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:**

शुभ अपराह्न, गवर्नर महोदय। मैं महंगाई की स्थिति को समझना चाहता हूं जिसे आपने समझाया है। आप यह भी कह रहे हैं कि चौथी तिमाही (ति4) में स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, जबकि तीसरी तिमाही (ति3) में ऊपरी जोखिम बना हुआ है। पिछली बार आपने घोड़े को अस्तबल में वापस लाने का उल्लेख किया था। अब स्थिति क्या है? क्या यह स्थिति है कि एक नियंत्रित ट्रॉट (तेज चाल) जारी रह सकती है, या आपको लगता है कि घोड़े को नियंत्रित करने के लिए आपको और कसकर लगाम पकड़नी होगी?

**शक्तिकान्त दास:**

घोड़े ने भागने का बहुत बहादुरी से प्रयास किया है। हमारा प्रयास उसे कसकर लगाम में रखने का है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। क्या अब मैं एनडीटीवी प्रॉफिट से श्री विश्वनाथ नायर को आमंत्रित करूँ?

**विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:**

नमस्कार, गवर्नर महोदय। पहला प्रश्न यह है कि आपने उल्लेख किया कि यदि विकास कम स्तर पर बना रहता है, तो आपको नीतिगत समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरी तिमाही कमजोर दिख रही थी, हालांकि वित्त वर्ष का शेष भाग बेहतर दिख सकता है। आपने विकास के अनुमान में जो कटौती की है, वह महंगाई के अनुमान में वृद्धि की तुलना में अधिक तीव्र है। मैं फिर भी यह समझना चाहता हूँ कि यथास्थिति क्यों बनाए रखी गयी, क्योंकि यह स्पष्ट है कि आपकी टिप्पणियों में विकास का पक्ष है।

**शक्तिकान्त दास:**

नहीं, चाहे मेरे पास विकास का पक्षपात हो या महंगाई का, मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या करना आपका काम है। लेकिन यदि आप याद करें, तो इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता, मैंने कुछ तात्कालिक उद्घाटन टिप्पणियाँ कीं, जिनमें मैंने स्पष्ट रूप से अपनी दृष्टिकोण की व्याख्या की कि मौद्रिक नीति क्यों महत्वपूर्ण है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में रिज़र्व बैंक को दिया गया जनादेश वास्तव में क्या है। प्रावधान बहुत स्पष्ट है और हमारा प्रयास हमेशा कानूनी प्रावधान का पालन करने का रहा है, जो महंगाई और विकास दोनों के संबंध में हमें दिया गया जनादेश है। हमारा प्रयास इसे अक्षरशः और भावना के अनुरूप पालन करना है। आप जानते हैं, एक केंद्रीय बैंक के कार्यकाल में आकस्मिक प्रतिक्रियाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। हमें अधिक विश्वसनीय साक्ष्यों की आवश्यकता है। हमें इस बारे में अधिक साक्ष्यों की आवश्यकता है कि परिदृश्य कैसा होने की संभावना है और उस आकलन के आधार पर, समय पर कार्रवाई करना हमारा प्रयास रहता है। चाहे वह कोई भी कार्रवाई हो - मैं दर कटौती या किसी अन्य विशेष कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ - हमारी प्रत्येक कार्रवाई का समयबद्धता अच्छी तरह से होना चाहिए और यह परिदृश्य पर निर्भर करता है। आकस्मिक प्रतिक्रिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी आकस्मिक प्रतिक्रिया ले सकते हैं जिसे आपको बाद में वापस लेना पड़ सकता है। इसलिए, आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना है कि हमारा प्रयास हमेशा वक्र के अनुरूप रहने का रहा है, कभी भी वक्र के पीछे नहीं गिरने का, और मुझे लगता है कि हम उस प्रवृत्ति को बनाए रख रहे हैं।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अब, मैं जी बिजनेस से श्री ब्रजेश कुमार को आमंत्रित करता हूँ।

**ब्रजेश कुमार, जी बिजनेस:**

सर, जैसा कि हर बार होता है, हम खाद्य महंगाई को लेकर चिंतित हो जाते हैं; खाद्य महंगाई एक बड़ा घटक है जो आपके लक्ष्य को बाधित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में एक और बहस हुई थी कि क्या हमें खाद्य महंगाई के घटक को हटाने के बाद लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। तो, इस पर मेरा प्रश्न यह है कि आपूर्ति पक्ष को सुधारने के संबंध में आपने हाल के अतीत में सरकार के साथ किस प्रकार की चर्चा की? और आर्थिक सर्वेक्षण का यह मत कि हमें खाद्य महंगाई को हटाने के बाद लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए; क्या इस पर कोई चर्चा हुई है?

**शक्तिकान्त दास:**

मैं सरकार के साथ होने वाली चर्चाओं को साझा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम महंगाई के संबंध में सरकार के साथ नियमित चर्चा में रहते हैं और आपूर्ति-पक्ष के उपायों के बारे में हमारी कई आंतरिक चर्चाएं होती हैं, जिनके बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। और जैसा कि आपने महंगाई लक्ष्यीकरण ढांचे और खाद्य महंगाई का प्रश्न उठाया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि शायद अगस्त नीति में, मैंने विस्तार से समझाया था कि हमें हेडलाइन महंगाई को लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए और हमें खाद्य महंगाई को क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, समग्र महंगाई हमारा लक्ष्य है। हम अपने आप प्रमुख महंगाई को लक्ष्य नहीं बना सकते, हम खाद्य महंगाई को लक्ष्य नहीं बना सकते, और हम ईंधन महंगाई को लक्ष्य नहीं बना सकते। हमें वही अनुसरण करना है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कानून के रूप में लिखा गया है। और हमारे पास यह विवेकाधिकार नहीं है कि हम अपनी इच्छानुसार इस या उस पर ध्यान केंद्रित करें। जो कानून है, हम उसका पालन करते हैं।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न सीएनबीसी टीवी18 से सुश्री लथा वेंकटेश का होगा।

**लथा वेंकटेश, सीएनबीसी टीवी18:**

धन्यवाद, पुनीत। सर, आपने कुछ बार कहा है कि विकास-महंगाई का संतुलन विकृत हो गया है और आपको इस संतुलन को बहाल करना है। क्या इसका मतलब यह है कि यह संतुलन विकास के पक्ष में विकृत था और आप महंगाई की ओर वापस जा रहे हैं, या

संतुलन महंगाई के पक्ष में विकृत था और अब यह विकास-समर्थक हो जाएगा? हम इस 'विकृति' के प्रश्न को कैसे समझें? और बस नकद आरक्षित अनुपात पर एक शब्द। यह केवल उस चलनिधि की देखभाल करने वाला है जो पहले ही प्रणाली से बाहर जा चुकी है। चौथी तिमाही (ति4) में, हम अभी भी नकद निकासी, संभावित डॉलर आवक और आरबीआई द्वारा डॉलर बिक्री को देख रहे हैं। तो, क्या आपके पास अभी भी खुले बाजार की कार्रवाई (ओएमओ) या इस तरह की कोई अन्य योजना तैयार है?

### शक्तिकान्त दास:

देखिए, हमारे पास तैयार जो भी कार्रवाई है, मैं उसे स्पष्ट रूप से बयान नहीं कर सकता। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति कैसे विकसित होती है। हम अगले कुछ महीनों में तंग तरलता स्थिति की उम्मीद करते हैं, जिन कारणों की मैंने पहले ही व्याख्या की है। एक तो यह कि हम प्रणाली से कर-संबंधी बहिर्वाह की उम्मीद करते हैं, दोनों प्रत्यक्ष कर दिसंबर के मध्य में और उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)। इसके साथ ही, मुद्रा परिचलन में वृद्धि की संभावना है क्योंकि व्यस्त ऋण सीजन चल रहा है, कृषि गतिविधियां अब बढ़ गई हैं और इसके लिए नकद की आवश्यकता होती है। यह फसल कटाई के सीजन में भी विलीन हो जाएगा, जिसके लिए भी नकद की आवश्यकता होती है। इसलिए, परिचलन में मुद्रा भी बढ़ने की संभावना है। और फिर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पूंजी बहिर्वाह की महत्वपूर्ण मात्रा रही है। अर्थात्, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बाहर निकलने के कारण विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह हुआ है। इसलिए, डॉलर आवक के आपके बिंदु के संबंध में, यह वर्तमान में मात्रात्मक रूप से आंकना कठिन है। हमारा आकलन यह है कि तरलता स्थितियां तंग बनी रहेंगी और आइए हम इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि सीआरआर में वृद्धि कुछ समय पहले, मुझे लगता है कि यदि मुझे सही याद है, तो अप्रैल 2022 की नीति में की गई थी। मुझे लगता है कि उस नीति में, हमने यह किया था। यह एक अस्थायी उपाय था। इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब इसे सामान्य करने का समय था। और विकास-महंगाई संतुलन के संबंध में, मैंने 'विकृत' नहीं कहा, मैंने बस 'असंतुलित' कहा था। और मुझे लगता है कि वक्तव्य में मैंने एक अलग शब्द का प्रयोग किया है। तो, मूल रूप से हमारा क्या मतलब है कि पिछली बार हमने कहा था कि विकास-महंगाई का संतुलन अच्छी तरह स्थापित था। 'अच्छी तरह स्थापित' का अर्थ है कि वृद्धि उस तिमाही के साथ-साथ पूरे वर्ष के लिए भी अच्छी लग रही थी। महंगाई का परिदृश्य भी, हमें पता था कि सितंबर और अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े अधिक होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मौसम के कारक और अन्य कारकों के कारण सितंबर और अक्टूबर में खाद्य महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई। सितंबर के आंकड़े मोटे तौर पर हमारे अनुमान से थोड़े अधिक थे। अक्टूबर के लिए भी हमने इसे अधिक होने की उम्मीद की थी। लेकिन वास्तविक संख्या हमारे अनुमान से थोड़ी अधिक आई। इसलिए, महंगाई हमारी उम्मीद से

अधिक, थोड़ी अधिक थी। और वृद्धि भी मंद हुई है। हमने संख्याएं दी हैं। तो, वृद्धि और महंगाई के बीच की गतिशीलता का 'अच्छी तरह स्थापित' चरित्र, कुछ असंतुलित हो गया है। अब हमारा प्रयास उस संतुलन को बहाल करना है, जिसका मूल अर्थ यह है कि हम महंगाई को लक्ष्य के करीब लाना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि वृद्धि बढ़े। और मुझे लगता है कि हमारे अनुमान, हमारा आकलन भी यह दर्शाता है कि वृद्धि बढ़ रही है। इसलिए, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमें वृद्धि और महंगाई के बीच उस संतुलन को बनाए रखना होगा। बस इतना ही। धन्यवाद।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न टाइम्स ऑफ इंडिया से श्री मयूर शेट्टी का होगा।

**मयूर शेट्टी, टाइम्स ऑफ इंडिया:**

धन्यवाद, सर। मेरा मूल प्रश्न इस सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े पर था, जो एक आश्चर्य के रूप में आए, जिस पर मनोजित ने पूछ लिया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपके कार्यकाल के दौरान कुछ संकट आए हैं, और उन समय में रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ समन्वय किया है, जो बहुत अच्छी तरह काम किया है। चूंकि अब अनिश्चितता एक स्थायी स्थिति बन गई है, तो क्या आपको लगता है कि इस समन्वय को जारी रखने की गुंजाइश है? विशेष रूप से जबकि, जैसा कि आपने कहा, महंगाई का जनदेश कानून में अंकित है, और सरकार की ओर से यह अपेक्षा है कि वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? और साथ ही, आप लोग अपनी कार्रवाइयों पर कोई अग्रिम मार्गदर्शन क्यों नहीं देते, जैसा कि फेड देता है? तो, क्या आपको लगता है कि समन्वय के लिए अधिक गुंजाइश है?

**शक्तिकान्त दास:**

क्या? (अग्रिम मार्गदर्शन पर)?

**मयूर शेट्टी, टाइम्स ऑफ इंडिया:**

जी, फेड की तरह अपनी कार्रवाइयों पर कोई अग्रिम मार्गदर्शन। तो, क्या आपको लगता है कि समन्वय के लिए अधिक गुंजाइश है?

**शक्तिकान्त दास:**

नहीं, मुझे लगता है कि समन्वय रहा है, समन्वय है, और समन्वय बना रहेगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और यह जारी रहती है। जब भी हमारे पास कोई विचार या चिंता होती है, हम हमेशा उसे सरकार के साथ साझा करते हैं। यह संलग्नता और समन्वय जारी रहता

है। वास्तव में, अपने एक हालिया भाषण में, जो हमने मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में दिया था, जिसमें ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने भाग लिया था, मैंने राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय के महत्व को रेखांकित किया था। अतः, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसने अपनी काबिलियत साबित की है। इसने कोविड के तनावपूर्ण समय के दौरान और उसके बाद, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और महंगाई अचानक बढ़ गई, अपनी मजबूती साबित की है। अतः, समन्वय जारी रहता है।

### **पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न रॉयटर्स से सुश्री स्वाति भट्ट का होगा।

### **स्वाति भट्ट, रॉयटर्स:**

धन्यवाद, सर। हमने देखा है कि वृद्धि के आंकड़े तेजी से कम आए हैं। 5.4% का आंकड़ा एक झटका था। आपने अगली दो तिमाहियों के लिए अपने वृद्धि अनुमानों को भी कम किया है, जबकि महंगाई उच्च है। क्या यह कहना उचित होगा कि भारत अब 'स्टैगफ्लेशन' (मंदी के साथ महंगाई) के चरण में प्रवेश कर गया है? और इन वृद्धि के आंकड़ों को देखते हुए, क्या भारत की प्रवृत्ति वृद्धि 7.5-8% के स्तर से कम होकर 6.5% के करीब आ रही है? क्या भारत की प्रवृत्ति वृद्धि उससे कहीं कम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं?

### **शक्तिकान्त दास:**

मैं यह प्रश्न उप गवर्नर, माइकल पत्रा जी को सौंपता हूँ। लेकिन मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि भाग-बी में हमारे अतिरिक्त उपायों के रूप में कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। मुझे लगता है कि उन पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे व्यापक दर्शकों के लिए उपयोगी होंगे।

### **माइकल डी. पत्रा:**

जैसा कि मैंने समझाया कि दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में मंदी एक विशेष कारकों के समूह के कारण है। अब, केवल एक डेटा पॉइंट के आधार पर प्रवृत्ति दर पर निर्णय लेना उचित नहीं है। जो 8% व्यक्त किया गया था, वह कोई प्रवृत्ति नहीं थी। यह केवल 2021 से 2024 तक का औसत था। और दुनिया भर में हर देश के लिए, 2025 और 2026 के लिए जो अनुमान बनाए जा रहे हैं, वे निहित रूप से महामारी से उछाल के लिए चक्रीय सुधार कर रहे हैं। इसलिए, जब हमने अपने प्रारंभिक प्रक्षेपण बनाए थे, तो वे 8% पर नहीं थे। वे 7.2% थे। और साथ ही, मौद्रिक नीति रिपोर्ट में, हमने 2026 के लिए एक प्रक्षेपण दिया था, जो वही चक्रीय सुधार था। इसके बाद, जब यह सुधार पूरा हो जाएगा, तो यह वापस एक प्रवृत्ति की ओर लौट आएगा और हमें अभी उस प्रवृत्ति के डेटा पॉइंट्स देखने

बाकी हैं। गवर्नर जो कह रहे हैं वह यह है कि 2021 से 2024 के बीच का औसत 8% था। अब, यदि आप वर्ष के दूसरे छमाही के प्रक्षेपणों को देखें, तो वृद्धि की ऊपरी दर की ओर वापसी हो रही है - 6.9%, 7.3% - और यह 2026 तक जारी रहती है। इसलिए, हमें उम्मीद है कि हम फिर से उस स्तर तक पहुंचेंगे।

### **पुनीत पंचोलो:**

धन्यवाद, महोदय। अगला प्रश्न मनीकंट्रोल से सुश्री हंसिनी कार्तिक का होगा।

### **हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:**

नमस्ते। सीआरआर कम करने का वास्तविक तर्क क्या था? प्रश्न इस संदर्भ में है कि निरपेक्ष शब्दों में, हमारे पास वैसी कोई चलनिधि की कमी नहीं है। और यदि मैं इसे बैंकिंग दृष्टिकोण से देखूँ, तो मुझे लगता है कि इस समय रेपो दर में कटौती की तुलना में सीआरआर में कटौती बैंकों को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देगी कि उन्हें मार्जिन के साथ ज्यादा समझौता न करना पड़े, यह देखते हुए कि पिछले तीन-चार तिमाहियों से बैंकों की लाभप्रदता भी प्रभावित रही है। क्या जब आपने सीआरआर कटौती शुरू की, तो यह भी आपकी सोच का हिस्सा था? और इस तरह, बैंक उधार भी सुस्त है। तो, क्या आपका मानना है कि यह उन्हें उधार देने के लिए अधिक धन मुक्त करेगा या उधार बढ़ाएगा?

### **शक्तिकान्त दास:**

देखिए, सीआरआर कटौती के बारे में, मैंने बस कुछ देर पहले समझाया कि हमने इसे सामान्य किया है। और इसे सामान्य करने का समय आ गया था। यह एक अस्थायी उपाय था। इसलिए, हमने इसे सामान्य कर दिया है। बैंक सीआरआर की राशि के साथ क्या करते हैं, यह पूरी तरह से उनका निर्णय है। चाहे वे इसका उपयोग ऋण देने के लिए करें या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, यह उनका निर्णय है। और तरलता के संदर्भ में, यह आज अधिशेष है। यह आज अधिशेष है। शायद सोमवार को, अगले सप्ताह भी दो-तीन दिन, यह अधिशेष रहने की संभावना है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां इस महीने के बाद के हिस्से, दिसंबर में, और जनवरी और शायद फरवरी तक तरलता बहुत तंग होने वाली है। इसलिए, हमने सोचा कि सीआरआर के स्तर को सामान्य करने का समय आ गया है। और बैंकों के बारे में आपके द्वारा उठाए गए अन्य प्रश्नों के संदर्भ में, हम मौद्रिक नीति या तरलता के निर्णय बैंकों की बैलेंस शीट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाते हैं। हमारी नीतियां वृद्धि-महंगाई की गतिशीलता द्वारा संचालित होती हैं। हमारी नीतियां अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से संचालित होती हैं। बैंकों आदि में जो भी मुद्दे हैं, उनकी देखरेख रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी अंग के माध्यम से की जाती है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अब, मैं पीटीआई से श्री आशीष अगाशे को आमंत्रित करूंगा।

**आशीष अगाशे, पीटीआई:**

धन्यवाद, सर। सर, एफसीएनआर(बी) उपाय को लागू करने के लिए क्या प्रेरित किया? पिछली बार हमने कुछ छूट के बाद 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि आते हुए देखा था। इस बार, क्या यह अनुमान है कि कितनी अतिरिक्त राशि प्रवाहित होगी? आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?

**एम. राजेश्वर राव:**

ये उपाय पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं, और यह परिपत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अनिवासी भारतीयों या पात्र भारतीयों के लिए, जो एफसीएनआर(बी) में निवेश करने के पात्र हैं, भारत में अपनी जमा पूंजी बढ़ाने का अवसर है, और वर्तमान में यही मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

**शक्तिकान्त दास:**

और यह एक अस्थायी उपाय है, जो 31 मार्च तक लागू रहेगा।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, महोदय। अब, मैं ईटी नाउ स्वदेश से श्री अनुराग शाह को आमंत्रित करता हूँ।

**अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:**

प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, सर। आजकल वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा किए जाने वाले बीमा व्यवसाय के संबंध में चेतावनी दी है। हमने देखा है कि कुछ निजी और सार्वजनिक बैंक बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। कुछ मामलों में आरबीआई अनुमति देता है, तो कुछ में नहीं। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें बैंकों की 50% हिस्सेदारी भी है। तो, क्या आरबीआई मामला-दर-मामला आधार पर हिस्सेदारी की अनुमति देता है, या नियमों और विनियमों में कोई बदलाव हुआ है? एक ओर जहां हमें बीमा कंपनियों की पहुंच बढ़ानी है, जिसमें बैंकों की बड़ी भूमिका है, वहीं दूसरी ओर यदि कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसे कोई बैंक खरीदने में सक्षम नहीं है, तो क्या ऐसे मामलों में आरबीआई बैंकों को हिस्सेदारी खरीदने के लिए अस्थायी अनुमति देता है? क्या उन विनियमों में कोई बदलाव हुआ है? और जैसा कि आपने सूचित किया कि आप बहुत जल्द एक पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं और एक नई संचार रणनीति होगी, तो इसका उद्देश्य क्या है और आप किस दर्शक वर्ग को लक्षित कर रहे हैं?

**शक्तिकान्त दास:**

आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं। मैं यह कह रहा था कि अन्य विषयों पर भी प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर उप गवर्नर, राजेश्वर राव जी उत्तर देंगे।

**एम. राजेश्वर राव:**

जैसा कि आपने बीमा के बारे में पूछा, तो हमने एक मसौदा परिपत्र जारी किया है, जिसमें हमने उल्लेख किया है कि बैंक कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी रख सकते हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। इसी आधार पर भविष्य की कार्रवाई या विनियामक कार्रवाई की जाएगी। हम 'व्यवसाय के रूप' परिपत्र पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो यह मार्गदर्शन करेगा कि हम बैंकों की सहायक या सहयोगी कंपनियों में निवेश को कैसे देखते हैं।

**अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:**

सर, आपने भी बैंकों को उस तरीके से चेतावनी दी है जिस तरह वित्त मंत्री ने प्लेटफॉर्म पर गलत बिक्री के बारे में चेतावनी दी है?

**शक्तिकान्त दास:**

नहीं, इस संबंध में हमारे पास पहले से ही मौजूदा निर्देश हैं। स्पष्ट निर्देश या दिशा-निर्देश पहले से ही अस्तित्व में हैं। हमें इसके बारे में कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने पर्यवेक्षण के माध्यम से यह जांच करते हैं कि क्या आरबीआई के निर्देशों से कोई विचलन है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो हम कार्रवाई करते हैं।

**अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:**

पॉडकास्ट के बारे में?

**शक्तिकान्त दास:**

पॉडकास्ट एक नया माध्यम है और अब यह बहुत लोकप्रिय हो गया है। मुझे लगता है कि इसकी पहुंच, विशेषकर युवाओं के बीच, बहुत व्यापक है। इसलिए, हम समय की मांग के अनुरूप रहना चाहते हैं। इस मामले में भी, हमें वक्र से आगे रहना चाहिए। मूल रूप से, यह लोगों के व्यापक वर्ग के साथ संवाद करने का एक संचार उपकरण है। कभी-कभी विस्तृत साक्षात्कार देना आवश्यक नहीं हो सकता है। कभी-कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना आवश्यक नहीं हो सकता है। यदि आप किसी विशिष्ट मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, या कोई नया उपाय घोषित किया गया है जिसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है, तो पॉडकास्ट उन प्रकार की स्थितियों में सहायक होगा।

**पुनीत पंचोली:**

अगला प्रश्न ब्लूमबर्ग से श्री अनुप राँय का होगा।

**अनुप राँय, ब्लूमबर्ग:**

सर, आपने कहा कि वृद्धि में आई मंदी संभवतः समाप्त हो गई है और अगले छमाहे में वृद्धि बेहतर होगी, लेकिन साथ ही आप यह भी कह रहे हैं कि महंगाई का दबाव बना रहेगा, संभवतः उससे भी अधिक जितना हमने अब तक देखा है। क्या आप यह संकेत दे रहे हैं कि फरवरी में ब्याज दरों में कटौती करना जोखिम भरा हो सकता है?

**शक्तिकान्त दास:**

मैंने ब्याज दरों के भविष्य के चक्र के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अब, मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस से श्री सचिन कुमार को आमंत्रित करता हूँ।

**सचिन कुमार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:**

सर, असुरक्षित ऋणों में वृद्धि। यह पिछले कुछ महीनों में काफी कम हो गई है, लेकिन अब स्वर्ण ऋण का एक ऐसा क्षेत्र है जहां वृद्धि बहुत मजबूत है। तो, क्या आपको लगता है कि यह चिंता का विषय है और क्या उस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उसी प्रकार के उपायों की आवश्यकता हो सकती है?

**शक्तिकान्त दास:**

मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उप गवर्नर, स्वामिनाथन जी को आमंत्रित करता हूँ।

**स्वामीनाथन जे.:**

देखिए, उस समय जब हमने पिछले वर्ष कुछ अतिरिक्त सावधानीपूर्ण उपाय लिए थे, तब असुरक्षित ऋणों में वृद्धि को नियंत्रित करना मुख्य उद्देश्य था। हमारा इरादा उस विशिष्ट खंड में दिखाई दे रहे अत्यधिक उत्साह को रोकना था, ताकि किसी संभावित तनाव या जोखिम के निर्माण से बचा जा सके। यही वह उद्देश्य था जिसके तहत हमने वह कदम उठाया था। अन्यथा, उत्पाद मिश्रण के संदर्भ में कि बैंकों को अपना व्यवसाय कैसे संचालित करना चाहिए, यह पूरी तरह से एक व्यावसायिक निर्णय है। चूंकि सोने का ऋण संपार्श्विक ऋण है, इसलिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने इसमें वृद्धि को प्राथमिकता दी है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों के प्रति उनके आचरण में निष्पक्षता हो और ऋण-मूल्य अनुपात, आय बनाम चुकौती दायित्वों आदि से संबंधित

उचित मानदंडों का पालन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा हो। अतः, हमारे निर्देश इस व्यवसाय के सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने की ओर अधिक केंद्रित हैं। वृद्धि या उत्पाद मिश्रण मूल रूप से बैंक के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे इसे कैसे आगे बढ़ाएं।

**सचिन कुमार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:**

आपके अनुसार 'अत्यधिक उत्साह' किसे योग्य ठहराता है?

**स्वामीनाथन जे.:**

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कम है या क्या अधिक है, कोई स्वर्णिम संख्याएं नहीं हैं। इसके अलावा, आपको आधार के संदर्भ में प्रतिशत को देखना होगा। जब हम लगभग 175 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण की बात करते हैं, तो एक लाख करोड़ से अधिक के सोने के ऋण का अनुपात क्या है? इसलिए, कभी-कभी प्रतिशत अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या पोर्टफोलियो का निर्माण जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। यही वह बात है जिस पर हम नजर रखेंगे। किसी भी स्थिति में, हम आने वाले आंकड़ों पर सतर्क रहेंगे और यदि किसी विवेकपूर्ण कदम के तहत कोई कार्रवाई शुरू करना आवश्यक हो, तो हम उचित समय पर वह कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में, हमारे विचार में आचरण के संबंध में दिया गया मार्गदर्शन पर्याप्त है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। क्या मैं अब द हिंदू बिजनेस लाइन से श्री पियूष शुक्ला को आमंत्रित कर सकता हूँ?

**पियूष शुक्ला, द हिंदू बिजनेस लाइन:**

शुभ अपराह्न, गवर्नर महोदय, उप गवर्नर महोदय। गवर्नर सर, मेरा पहला प्रश्न सचिन सर द्वारा सोने के ऋणों के संबंध में पूछे गए प्रश्न से संबंधित है। मेरा प्रश्न लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) पर है। कई एमएफआई कंपनियां उच्च बकाया और उच्च प्रावधान देख रही हैं। क्या आरबीआई स्वयं सहायता समूहों को लेकर चिंतित है? किसी ने उल्लेख किया कि केवल छह महीने का अनुभव होने पर भी उन्हें ऋण मिल जाता है। तो, क्या एमएफआई क्षेत्र में हम किसी प्रारंभिक तनाव के निर्माण को देख रहे हैं और इस पर आपके क्या विचार हैं? और अलग से, आपको इस बात का क्या भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष में 6.8% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल की जा सकती है? आपने जो संशोधित प्रक्षेपण किया है, क्योंकि नवंबर में हमने यूपीआई लेनदेन में 6%-7% की गिरावट देखी। मुझे पता

है कि यह एकमात्र संकेतक नहीं है, लेकिन माह-दर-माह यह 7% गिरा है और यह त्योहारों का महीना था, तो...?

### शक्तिकान्त दास:

सकल संख्याओं पर, मुझे लगता है कि मैंने विवरण में अपने वक्तव्य में और अब भी विस्तार से समझाया है। अब, हमें क्या भरोसा है या नहीं, यह आंकलन करना आपका काम है कि तीसरी तिमाही के लिए हमारे आंकड़े यथार्थवादी हैं या नहीं। हमने अपना आकलन किया है और हम कई कारकों को देखते हैं। यह केवल यूपीआई नहीं है, यह केवल कारकों में से एक है। लेकिन आपके प्रश्न के दूसरे भाग पर, यानी एमएफआई के संबंध में, मैं उप गवर्नर, स्वामीनाथन जी से उस प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करता हूँ।

### स्वामीनाथन जे.:

ये कुछ ऐसे खंड हैं जिनके बारे में हमने पिछली बार मौद्रिक नीति समिति के दौरान भी चर्चा की थी। दूसरी तिमाही (ति 2) के आंकड़ों में हमने देखा कि कुछ खंडों में फिसलन बढ़ी है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, यह हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि ये वे ही खंड थे जिनमें पिछले वर्ष असाधारण वृद्धि देखी गई थी और हमने उस पर कुछ सक्रिय उपाय किए थे। यदि आप याद करें, तो अगस्त की मौद्रिक नीति वक्तव्य में गवर्नर ने कहा था कि जिन खंडों में बढ़ी हुई फिसलन देखी जा रही है, वहां: (क) हमने बैंकों और एनबीएफसी से अपने ऋण स्वीकृति मानदंडों को मजबूत करने का अनुरोध किया है, और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि तनाव गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) में न बदले, वे अपनी वसूली प्रयासों को तेज करें। इसी थीम पर, जहां भी हमें कोई असाधारण व्यवहार दिखाई देता है, हम संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं। प्रणाली स्तर पर, तनाव में 20-30 आधार अंक(bps) की वृद्धि अभी बड़ी चिंता का विषय नहीं है; हमें विश्वास है कि संस्थाएं इसे संभाल लेंगी। जिन विशिष्ट संस्थाओं में ये आंकड़े थोड़े असाधारण हैं, हम उनसे द्विपक्षीय रूप से निपटते हैं और यह जांचते हैं कि वे तनाव को व्यापक रूप से न फैलने देने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। तीसरा, स्वयं-विनियामक संगठनों (एसआरओ) के माध्यम से, हमारे पास पर्याप्त उपाय उपलब्ध हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एमएफआई क्षेत्र में एसआरओ अपने सदस्यों को आरबीआई के सावधानीपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए संवेदनशील बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि घरेलू आय के आकलन और शुद्ध मासिक आय के सापेक्ष चुकौती दायित्वों का कड़ाई से पालन किया जाए। जैसा कि गवर्नर ने पहले कहा, 'पुश इफेक्ट'(धकेलने का प्रभाव)से बचने के लिए केवल मांग के अनुरूप प्रतिक्रिया दें, न कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऋण दें। मुझे लगता है कि ये 3-4 मुख्य संदेश हैं जो हमने पिछले 2-3 महीनों में दिए हैं। मेरा मानना है कि इस खंड में संतुलन बहाल करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए।

**टी. रबी शंकर:**

यूपीआई आंकड़ों के संदर्भ में, मुझे लगता है कि हमें इसका अतिरंजित विश्लेषण नहीं करना चाहिए। पिछले महीने त्योहारों के समय के कारण एक असाधारण वृद्धि देखी गई थी, जो इस महीने सुधर गई है। इसलिए, मेरी उम्मीद है कि आगे भी यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, महोदय। अब, मैं द हिंदू से श्री ललतेंदु मिश्रा को आमंत्रित करता हूं।

**ललतेंदु मिश्रा, द हिंदू:**

शुभ अपराह्न, गवर्नर महोदय। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर भारत जैसे ब्रिक्स देशों पर शुल्क बाधाएं लगाने की धमकी दी है। क्या इसका हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा या यह चिंता का विषय है?

**शक्तिकान्त दास:**

सबसे पहले, आइए हम समय से पहले कोई निष्कर्ष न निकालें... नीति आने दें। जहां तक ब्रिक्स का प्रश्न है - आप शायद ब्रिक्स मुद्रा और उससे जुड़ी चर्चा का संदर्भ दे रहे हैं। ब्रिक्स मुद्रा का विचार ब्रिक्स देशों में से एक सदस्य द्वारा उठाया गया था और उस पर चर्चा हुई थी। इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यूरोज़ोन के विपरीत, जहां एकल मुद्रा है और देश भौगोलिक रूप से सटे हुए हैं, ब्रिक्स देशों का भौगोलिक विस्तार बहुत व्यापक है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। अडालरीकरण (डी-डालराइज़ेशन) या डॉलर पर निर्भरता कम करने के संदर्भ में, भारत ने इस दिशा में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसका विशिष्ट उद्देश्य अडालरीकरण हो। हमने केवल वोस्ट्रो खातों को खोलने की अनुमति दी है और अब तक दो देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए समझौते किए हैं। इसका मूल उद्देश्य हमारे भारतीय व्यापार को जोखिम-मुक्त करना है। किसी एक मुद्रा पर निर्भरता कभी-कभी उसकी मूल्य-वृद्धि या मूल्यहास के कारण समस्याग्रस्त हो सकती है। इसलिए, अपने व्यापार को जोखिम-मुक्त करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अडालरीकरण निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य नहीं है। यह बिल्कुल भी चर्चा के केंद्र में नहीं है। मुझे लगता है कि यह मीडिया के कुछ वर्गों में चल रहा एक वर्णन मात्र है। हमारा प्रयास मूल रूप से अपने व्यापार को जोखिम-मुक्त करना है। कोई भी वि-डॉलराइज़ेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है या सोच नहीं रहा है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अब, मैं द इकोनॉमिक टाइम्स से सुश्री संगीता मेहता को आमंत्रित करता हूँ।

**संगीता मेहता, द इकोनॉमिक टाइम्स:**

सर, क्या आप नीति में बताए गए स्टैंडर्ड ऑफर रेफरेंस रेट (मानक प्रस्ताव संदर्भ दर) को पेश करने के पीछे की अपनी सोच साझा कर सकते हैं? और क्या आप मसौदा दिशानिर्देशों की समय-सीमा के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि परियोजना वित्त, एलसीआर, ईसीएल और जलवायु वित्त जैसे लगभग चार विषयों पर पहले ही चर्चा हो रही है?

**माइकल डी. पात्रा:**

वर्तमान में, हमारे पास एफबीआईएल द्वारा निर्धारित दो बेंचमार्क हैं। एक मिबोर(एमआईबीओआर) है, जो बिना-संपार्श्विक लेनदेन से संबंधित है, और दूसरा एमआरओआर है, जो बाजार-रेपो पर आधारित है। लेकिन टीआरईपीएस, जो बाजार का 60% हिस्सा है, उस सूचकांक में शामिल नहीं है। इसलिए, जो नया सूचकांक हम अब ला रहे हैं, वह सभी सुरक्षित लेनदेन को कवर करेगा। यही मुख्य बिंदु है।

**शक्तिकान्त दास:**

और दूसरे भाग के लिए, मैं उप गवर्नर राजेश्वर राव जी से विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध करता हूँ।

**एम. राजेश्वर राव:**

बैंकिंग प्रणाली के लिए ये दिशानिर्देश काफी बड़े बदलाव हैं। इसलिए, हमें इन सभी दिशानिर्देशों पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिली है, जिनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। हम इन दिशानिर्देशों को लागू करने के तरीके को अंतिम रूप देंगे, लेकिन हम इस प्रक्रिया में हैं और कुछ दृष्टिकोणों को अंतिम रूप देने के करीब हैं। मैं कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दे सकता। हम इसे यथाशीघ्र करेंगे।

**शक्तिकान्त दास:**

हमने एक बहुत ही परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। ये सभी उपाय बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। इसलिए, हम बहुत सावधानी और नपे-तुले तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो बैंकों और कई अन्य हितधारकों द्वारा उठाए गए सुझावों और अन्य मुद्दों को ध्यान में रखता है। हम बहुत सावधानी और सतर्कता से आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जब इन्हें लागू किया जाए, तो कार्यान्वयन यथासंभव गैर-विघटनकारी हो।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। अब, मैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से श्री बेन जोस को आमंत्रित करता हूँ।

**बेन जोस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस:**

सर, उम्मीद है कि अगली मौद्रिक नीति में भी आपको देखने को मिलेगा। आपके छह वर्षों के कार्यकाल के लिए बधाई। और पात्रा सर, हम आपको अगली नीति में याद करेंगे। मेरा प्रश्न ललतेंदु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न से जुड़ा है। रुपया दबाव में रहा है और यदि ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शुल्क युद्ध होता है, मान लीजिए भारतीय निर्यात पर 10% शुल्क लगता है, तो रुपए पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?

**माइकल डी. पात्रा:**

यदि परिकल्पनात्मक रूप से ऐसा शुल्क लगता है, तो यह एक अलग-थलग घटना नहीं होगी। इसके आसपास अन्य घटनाएं भी होंगी। उदाहरण के लिए, कहा जा रहा है कि शायद चीन मुद्रा का अवमूल्यन करके या प्रतिकारी शुल्क लगाकर प्रतिक्रिया दे सकता है। इसलिए, इस समय यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सा एकपक्षीय कदम होगा और उसका एकपक्षीय प्रभाव क्या होगा। हमें सामान्य संतुलन प्रभावों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद, सर। और अंत में, मैं इन्फॉर्मिस्ट से श्री सिद्धार्थ उपासनी को आमंत्रित करता हूँ।

**सिद्धार्थ उपासनी, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया:**

धन्यवाद, सर। नमस्कार गवर्नर महोदय। कुछ महीने पहले, डॉ. पात्रा द्वारा सह-लिखित एक पेपर में कहा गया था कि मई 2022 से हुई ब्याज दरों में वृद्धि ने विकास पर लगभग 160 आधार अंकका नकारात्मक प्रभाव डाला है। तो, क्या महंगाई कम करने के लिए बहुत अधिक विकास की बलि दी गई है? और क्या ये ब्याज दरों में वृद्धि और रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखना भविष्य में विकास को प्रभावित करना जारी रखेगा? दूसरा, क्या विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के दबाव को कम करने के लिए एफसीएनआर(बी) की सीमा बढ़ाई गई है? क्योंकि मौद्रिक नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नीति कुछ हद तक विरोधाभासी लग रहे हैं, और हस्तक्षेपों ने रुपए के चलनिधित्व को काफी कम कर दिया है। क्या यह भी एक विचारणीय बिंदु था?

**शक्तिकांत दास:**

चूंकि वह पेपर डॉ. माइकल पात्रा द्वारा लिखा गया था, इसलिए मैं उन्हें ही इसका उत्तर देने के लिए कहूंगा।

### माइकल डी. पात्रा:

मुझे खुशी है कि आपने वह पेपर पढ़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा। उसमें क्या कहा गया है कि 250 आधार अंक की संचयी ब्याज दर वृद्धि ने समग्र मांग के माध्यम से महंगाई को 160 आधार अंक तक कम किया। लेकिन महंगाई अप्रैल में 7.8% से घटकर हाल ही में अगस्त में 3.8% रह गई। तो, कुल 320 आधार अंक की गिरावट में से केवल 160 आधार अंक मौद्रिक नीति के कारण हैं। उसी पेपर में आप ऐसे चार्ट देखेंगे जो ब्याज दर में बदलाव का उत्पादन और महंगाई पर प्रभाव दिखाते हैं। उत्पादन पर प्रभाव दर बढ़ने के बाद शुरू होता है और दर बढ़ने के बाद तीसरी तिमाही में अपने चरम पर पहुंचता है; चौथी तिमाही में यह स्थिर हो जाता है और उसके बाद इसका प्रभाव कम होने लगता है। तो, यदि आप ब्याज दरों में वृद्धि के चक्र को देखें, तो संचयी चरम जुलाई-सितंबर 2022 की तिमाही में था। वहां से उत्पादन पर प्रभाव के लिए चार तिमाहियां लें, तो वह जुलाई-सितंबर 2023 बनती है। उसके बाद उत्पादन वापस बढ़ने लगता है। महंगाई पर प्रभाव 10 तिमाहियों तक बना रहता है। इसलिए, अब तक उत्पादन वापस बढ़ने लगा है और वास्तव में यह उस स्तर को पार कर चुका है जिसे हम 'संभावित स्तर' कहते हैं। इसलिए, दूसरी तिमाही की विकास दर में धीमी गति को उस ब्याज दर वृद्धि से जोड़ना, मेरे विचार में, तर्क को बहुत अधिक खींचना होगा।

### पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। बस mint से गोपिका गोपाकुमार का एक अंतिम प्रश्न।

### गोपिका गोपाकुमार, द मिंट:

उन्हीं के प्रश्न में जोड़ते हुए, क्या विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर यह चिंता थी, देखते हुए कि पिछले दो महीनों में हमने जिस प्रकार के बहिर्वाह देखे हैं और भविष्य में भी इसी मात्रा के बहिर्वाह की उम्मीद है? क्या एफसीएनआर(बी) सीमा बढ़ाने के पीछे यही विचार था? और क्या मुद्रा की रक्षा के लिए और अधिक उपाय किए जाएंगे? मेरा दूसरा प्रश्न अत्यधिक ब्याज दरों पर है। आरबीआई ने अत्यधिक ब्याज दरों को लेकर काफी चिंता व्यक्त की है। अब, रिजर्व बैंक ने 'सिद्धांत-आधारित विनियमन' का पालन किया है और ब्याज दरों पर किसी भी प्रकार की ऊपरी सीमा को हटा दिया है। लेकिन उद्योग में, विशेषकर एमएफआई और असुरक्षित ऋणों में, जो चिंताएं बढ़ रही हैं, क्या उधार दरों के संदर्भ में कोई सीमा या थ्रेशोल्ड(निर्धारित सीमा) परिभाषित करने की आवश्यकता है?

### शक्तिकांत दास:

लेकिन उससे पहले, एफसीएनआर(बी) के संबंध में, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी काफी मजबूत हैं। पिछले कुछ महीनों में भंडार में जो

कमी आई है, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा मूल्यांकन हानि के कारण है। फिर भी, हमारे भंडार पर्याप्त हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार, हमारे पास लगभग 656 अरब अमेरिकी डॉलर या उससे कुछ अधिक हैं (सटीक संख्या मुझे याद नहीं है), लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी काफी पर्याप्त हैं। हम किसी भी प्रकार के प्रसार-प्रभाव(स्पिलओवर) से निपटने को लेकर आश्वस्त हैं। आपने उल्लेख किया कि रिजर्व बैंक बहिर्वाह को लेकर चिंतित है। देखिए, किसी ने कहा कि प्रमुख पूंजी अंतर्वाह (इनफ्लोज) की उम्मीद है, तो विदेशी मुद्रा बाजार भविष्य में कैसे व्यवहार करेगा? हम वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकते, हमें देखना होगा। बहुत सी अनिश्चितताएं हैं—अमेरिका में नया प्रशासन सत्ता में आने वाला है, अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी। इसलिए, यह एक बहुत ही गतिशील रूप से विकसित होने वाली स्थिति है। आवश्यकता के अनुसार, हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए, वर्तमान क्षण में हमें कोई चिंता नहीं है। एफसीएनआर(बी) सीमा बढ़ाना एक सुविधा है जो हमने अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने और एनआरआई को निवेश का अवसर प्रदान करने के लिए दी है। (मुझे लगता है कि दो प्रश्नों के कारण मैं थोड़ा भटक गया, क्या आपने एफसीएनआर(बी) के संबंध में और कुछ पूछा था?)

**गोपिका गोपाकुमार, द मिंट:**

क्या और अधिक उपाय होंगे?

**शक्तिकांत दास:**

अधिक उपायों के बारे में, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मैं अभी विस्तार से नहीं बता सकता। आवश्यकता पड़ने पर, हम यथासमय अधिक उपाय करेंगे। लेकिन विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर, मैं बहुत स्पष्ट और जोरदार ढंग से कहना चाहता हूँ कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हैं। मैंने अपने वक्तव्य में आरबीआई की विदेशी मुद्रा प्रबंधन नीति के तर्क को समझाने के लिए दो पैराग्राफ समर्पित किए हैं। इसका फोकस केवल स्पिलओवर से निपटना नहीं है, बल्कि यह घरेलू प्रणाली की स्थिरता - समष्टि आर्थिक स्थिरता) और वित्तीय स्थिरता - को बनाए रखने की रिजर्व बैंक की नीति का एक अनिवार्य हिस्सा है।

**स्वामीनाथन जे.:**

देखिए, जैसा कि आप याद करेंगे, रिजर्व बैंक ने व्यापक परामर्श के बाद प्रशासित ब्याज दरों को विनियमित कर दिया है। यह स्वतंत्रता अब बैंकों और एनबीएफसी के निदेशक मंडलों के पास है। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मंडलों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस स्वतंत्रता का उपयोग विवेकपूर्ण और समझदारी से करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी मूल्य निर्धारण प्रथाएं, चाहे वे ब्याज दरों के संबंध में हों या शुल्क के, 'अत्यधिक' न मानी जाएं। इसी विनियम में हमने यह भी कहा है कि इसका मूल्यांकन

पर्यवेक्षीय आकलन के अधीन होगा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे आकलन के आधार पर, जहां भी हमें ऐसी प्रथाएं मिलीं जहां ग्राहक के हित खतरे में थे और निर्णय ग्राहक के हित की सुरक्षा के बजाय अधिकतर लाभ के उद्देश्यों से संचालित थे, हमने ऐसे संस्थानों को चिह्नित किया है। जैसा कि गवर्नर ने उल्लेख किया, हमने कई संस्थानों के साथ विस्तृत चर्चा की है। कई संस्थानों ने स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं कदम उठाए हैं, जबकि कुछ ऐसे संस्थान जो 'असामान्य' पाए गए, उन्हें हमने पर्यवेक्षी कार्रवाई के लिए अलग से चुना है। भविष्य में, उनकी स्थिति में सुधार के आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। आपके प्रश्न के तीसरे भाग के संबंध में कि क्या हम पुनर्विचार कर रहे हैं? मेरा मानना है कि इस समय, हम अभी भी उद्योग से यह अपेक्षा करते हैं कि वे स्वयं को सुधारें और उन्हें दी गई स्वतंत्रता का समझदारी से उपयोग करें, ताकि उनका व्यवसाय जिम्मेदारी से बढ़े, उनके आचरण में निष्पक्षता बनी रहे और ग्राहकों के साथ न्याय हो। हम वर्तमान में इसी दिशा में प्रयासरत रहेंगे।

#### **शक्तिकांत दास:**

समापन से पहले, एक घोषणा जो मैंने 'म्यूलहंटर.एआई' (फर्जी/ठगी वाले खातों का पता लगाने वाला साफ्टवेयर) के बारे में की थी। मुझे लगा कि इस पर कोई प्रश्न आएगा, लेकिन चूंकि नहीं आया, फिर भी इस जानकारी को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, मैं उप गवर्नर रबी शंकर से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में इसकी व्याख्या करें।

#### **टी. रबी शंकर:**

धन्यवाद, गवर्नर। और धन्यवाद कि आपने हस्तक्षेप किया, जिससे मुझे लंबे समय बाद एक सीधा प्रश्न पूछने का अवसर मिला। 'म्यूलहंटर.एआई' मूल रूप से एक बुनियादी ढांचे स्तर की व्यवस्था है जिसे हम बना रहे हैं। यह सभी बैंकों और अन्य भुगतान प्रणाली परिचालकों के डेटाबेस का उपयोग करेगा। इसका एआई इंजन इस विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी आदि की बहुत अधिक प्रभावी ढंग से पहचान कर सके। यदि आप धोखाधड़ी के आंकड़ों को देखें, तो धोखाधड़ी की संख्या और उसमें शामिल राशि दोनों बढ़ रही हैं, हालांकि प्रति लेनदेन धोखाधड़ी की संख्या वर्षों से कम हो रही है। लेकिन कुल संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं 'म्यूलहंटर.एआई' के संबंध में एक बिंदु स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में कुछ चर्चा थी कि कोई भी संस्था, कोई भी भुगतान प्रणाली संचालक, कोई भी बैंक, या कोई भी क्रेडिट कार्ड नेटवर्क अपनी स्वयं की धोखाधड़ी पहचान प्रणालियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। वे इस प्रणाली के अतिरिक्त अपनी प्रणालियों का उपयोग जारी रखेंगे। वास्तव में, हर व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता और अपने स्वयं के एआई इंजन के आधार पर नवाचार करने के लिए स्वतंत्र है। रिजर्व बैंक द्वारा 'म्यूलहंटर.एआई'

पेश करने का विचार एक बुनियादी ढांचे स्तर की सुविधा बनाना है जिसका उपयोग अन्य कर सकें। कई प्रतिभागी, विशेष रूप से कई छोटे बैंक, जो ऐसी प्रणालियों को विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं लगा सकते, वे वास्तव में इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि सुविकसित संस्थानों के लिए भी, यह एक आधार है जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं।

### **शक्तिकांत दास:**

धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी पुनीत पंचोली के समापन से पहले, मुझे बस एक जानकारी देनी है। यह 'RBI@90 क्विज़' के बारे में है, जिसे हमने इस वर्ष लॉन्च किया था। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने रिजर्व बैंक के 90वें वर्ष की याद में अगस्त इस वर्ष स्नातक छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की क्विज़ लॉन्च की थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि क्विज़ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। हम आज दोपहर 2:30 बजे मुंबई में राष्ट्रीय फाइनल आयोजित कर रहे हैं। इसे रिजर्व बैंक के यूट्यूब चैनल पर सीधे प्रसारित किया जाएगा। मैं सभी को, विशेष रूप से सभी दर्शकों को, इस रोमांचक प्रतियोगिता को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। धन्यवाद।

### **पुनीत पंचोली:**

बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। इसके साथ ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन करते हैं। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे बाईं ओर स्थित द्वार से बाहर निकलें। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आपका दिन शुभ हो।